प्रत्येक सोमवार को हल्द्वानी से प्रकाशित

भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक कार्यालय से प्रदत्त पंजीयन संख्या : UTTHIN/2017/73662

कुमाऊं जनसन्देश

www.kumaonjansandesh.com

वर्ष – 9 अंक – 39 हल्द्वानी(नैनीताल) सोमवार 24 अगस्त 2026 पृष्ठ – 4 मूल्य – 2.00 रुपया

विकास के पथ पर बढ़ रहा लालकुआं

सांसद अजय भट्ट ने किया स्वागत द्वार व तिरंगा लाइट का लोकार्पण

कुमाऊं जनसन्देश ब्यूरो

लालकुआं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नगर पंचायत लालकुआं में आयोजित समारोह में नगर के दोनों प्रवेश द्वारों पर नवनिर्मित स्वागत द्वार एवं तिरंगा लाइट का लोकार्पण किया गया। मुख्य अतिथि सांसद अजय भट्ट ने नगर पंचायत अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह लोटनी की अध्यक्षता में बोर्ड सदस्यों एवं गणमान्य नागरिकों की मौजूदगी में इन विकास कार्यों का विधिवत उद्घाटन किया।

नगर पंचायत अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह लोटनी ने कहा कि नगर के सौंदर्यीकरण और विकास को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। दोनों प्रवेश द्वारों के निर्माण से लालकुआं को नई पहचान मिलेगी, जबकि तिरंगा लाइट के माध्यम से राष्ट्रीय भावना और देशभक्ति का संदेश भी प्रदर्शित होगा।लोकार्पण के बाद नगर पंचायत अध्यक्ष ने सांसद अजय भट्ट के साथ नगर के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में मूलभूत सुविधाओं, यातायात व्यवस्था, विद्युत लाइन, रेलवे क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों, बाईपास निर्माण और भविष्य की विकास योजनाओं पर विस्तार से विचार–विमर्श हुआ।

अध्यक्ष लोटनी ने आवासीय क्षेत्र के बीच से गुजर रही 33 केवी विद्युत लाइन को स्थानांतरित किए जाने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि विद्युत लाइन के कारण सुरक्षा संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और इसका समाधान जरूरी है। सांसद अजय भट्ट ने इस मामले में मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इसे मुख्यमंत्री घोषणा में शामिल कराने का आश्वासन दिया। बैठक में लालकुआं रेलवे क्षेत्र में लगभग 25 करोड़ रुपये की लागत से चल रहे विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्यों की जानकारी भी साझा की गई। नगर पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि रेलवे क्षेत्र का विकास लालकुआं की समग्र सुंदरता और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नगर में बढ़ते यातायात दबाव और जाम की समस्या को देखते हुए अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह लोटनी ने लालकुआं बाईपास निर्माण का मुद्दा भी सांसद के समक्ष रखा। उन्होंने कहा कि भारी वाहनों के नगर के बीच से गुजरने के कारण नागरिकों को परेशानी होती है। बाईपास बनने से यातायात का दबाव कम होने के साथ ही नगरवासियों को जाम से राहत मिलेगी। सांसद अजय भट्ट ने इस विषय में आवश्यक पहल और सहयोग का आश्वासन दिया। वहीं, ग्रीन बाईपास को लेकर भी चर्चा हुई। सांसद ने बताया कि इससे क्षेत्र की सड़क कनेक्टिविटी बेहतर होने और लालकुआं से मुरादाबाद तक आवागमन का समय कम होने में मदद मिलेगी। अध्यक्ष ने कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी से व्यापार, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। नगर पंचायत अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह लोटनी ने कहा कि लालकुआं का विकास उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। नगर पंचायत का उद्देश्य केवल सौंदर्यीकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि बेहतर सड़क, यातायात, विद्युत व्यवस्था और मूलभूत नागरिक सुविधाओं से युक्त व्यवस्थित एवं विकसित नगर बनाना है। कार्यक्रम में बोर्ड सदस्य नेहा आर्य, धन सिंह बिष्ट, योगेश उपाध्याय, शबनम, सुरेश शाह, दीपा, हेमंत पांडे और भुवन पांडे सहित नामित सदस्य विनोद श्रीवास्तव, गौरव कपूर और तारा पांडे मौजूद रहे। इसके अलावा सांसद प्रतिनिधि लक्ष्मण सिंह खाती, पूर्व अध्यक्ष पवन कुमार चौहान, व्यापार मंडल अध्यक्ष दीवान सिंह बिष्ट, वरिष्ठ समाजसेवी संजीव शर्मा, अरुण जोशी, हरीश नैनवाल, बॉबी संभल, अशोक पाठक, दीपू दयाल, बी. भट्ट, रमाकांत और चंद्रशेखर सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

महापौर गजराज ने परखी शहर की मूलभूत व्यवस्थाएं

अधिकारियों को दिए विकास कार्यों में तेजी के दिए निर्देश

कुमाऊं जनसन्देश ब्यूरो

हल्द्वानी। नगर निगम क्षेत्र में जनसुविधाओं, शिक्षा व्यवस्था, गौवंश संरक्षण और विकास कार्यों को प्राथमिकता देते हुए महापौर ''गजराज बिष्ट'' ने राजपुरा स्थित गौशाला, नगर निगम इंटर कॉलेज काठगोदाम तथा वार्ड संख्या 22 की लाइन नंबर 12 में प्रस्तावित मीट बाजार स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया।

नगर निगम इंटर कॉलेज काठगोदाम में आयोजित बैठक में महापौर ने विद्यालय की व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान नगर आयुक्त एवं प्रधानाचार्यों के साथ छात्र–छात्राओं की सुविधाओं, शैक्षणिक व्यवस्था और विद्यालय परिसर से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। महापौर ने शौचालय भवनों के निर्माण, वर्तमान व्यवस्थाओं के जीर्णोद्धार और आवश्यक सुविधाओं के विस्तार के लिए शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों और शैक्षणिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए भी आवश्यक कदम उठाने को कहा। उन्होंने कहा कि बच्चों को बेहतर एवं सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना नगर निगम की प्राथमिक जिम्मेदारियों में शामिल है। महापौर ने राजपुरा स्थित गौशाला का औचक निरीक्षण कर गौवंश के लिए उपलब्ध व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।

साथ ही अनुबंधित संस्था को गौवंश के लिए पर्याप्त एवं गुणवत्तापूर्ण चारा, स्वच्छ पानी, आवश्यक दवाइयां तथा बेहतर सुरक्षा और देखरेख की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। महापौर ने स्पष्ट किया कि गौवंश की देखभाल में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी और संबंधित संस्था को निर्धारित मानकों का कड़ाई से पालन करना होगा।

निरीक्षण के अंतिम चरण में महापौर ने वार्ड संख्या 22, लाइन नंबर 12 में प्रस्तावित मीट बाजार की दुकानों के निर्माण के लिए चयनित स्थल का पार्षद ''मो. गुफरान, सलीम सैफी एवं हाजी राशिद'' के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान प्रस्तावित दुकानों के निर्माण, स्थल की उपयोगिता और आवश्यक व्यवस्थाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। महापौर ने नगर निगम के सहायक अभियंता ''नवल नौटियाल'' को आवश्यक प्रक्रिया में तेजी लाते हुए जल्द कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। महापौर गजराज बिष्ट ने कहा कि नगर निगम द्वारा ''शिक्षा, स्वच्छता, जनसुविधाओं, गौवंश संरक्षण और सुव्यवस्थित बाजार व्यवस्था'' से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। नगर निगम का उद्देश्य शहर के प्रत्येक क्षेत्र में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए स्वच्छ, सुरक्षित, सुव्यवस्थित और जनहितकारी हल्द्वानी–काठगोदाम का निर्माण करना है।

कृषि मंत्री जोशी ने मंडी बोर्ड की योजनाओं की समीक्षा

बजट समय पर खर्च करने के दिए निर्देश

कुमाऊं जनसन्देश ब्यूरो

हल्द्वानी। प्रदेश के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सोमवार को हल्द्वानी स्थित सर्किट हाउस में उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने नई मंडी नौगांव (उत्तरकाशी) के क्रियान्वयन सहित मंडी बोर्ड की विभिन्न योजनाओं एवं विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए। बैठक में मंत्री ने ई–नाम प्रणाली, मंडियों की वित्तीय स्थिति, मुख्यमंत्री घोषणाओं, कृषि उत्पादन क्षति सहायता योजना, किसानों की दुर्घटना सहायता योजना, कृषकों के बच्चों की छात्रवृत्ति योजना, नाबार्ड पोषित योजनाओं तथा मंगलौर और विकासनगर में प्रस्तावित कोल्ड स्टोरेज निर्माण की प्रगति की जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि मंडी बोर्ड की आय के लिए 175 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस पर कृषि मंत्री ने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए गंभीरता और प्राथमिकता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों को विभिन्न योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से मिले और मंडी बोर्ड से जुड़े विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए।मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को स्वीकृत बजट का निर्धारित समय–सीमा के भीतर शत–प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता एवं गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए तथा किसानों से जुड़ी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक प्राथमिकता के आधार पर पहुंचाया जाए। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने, कृषि उत्पादों के बेहतर विपणन और किसानों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्य कर रही है। मंडी व्यवस्था को मजबूत करने के साथ ही कोल्ड स्टोरेज और ई–नाम जैसी सुविधाओं का विस्तार किसानों के लिए लाभकारी साबित होगा। बैठक में अध्यक्ष प्रबंध निदेशक मंडी परिषद हेमंत कुमार वर्मा, वित्त नियंत्रक मंडी परिषद जुबक मोहन सक्सेना, महाप्रबंधक तकनीकी विजय कुमार, विपणन अधिकारी प्रवीण शर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

मंत्री कैड़ा ने सीएम के समक्ष रखी भीमताल विधानसभा क्षेत्र की समस्याएं

देहरादून में की मुलाकात

कुमाऊं जनसन्देश ब्यूरो

देहरादून/हल्द्वानी। कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा ने मुख्य मंत्री पुष्कर सिंह धामी से देहरादून में मुलाकात कर कहा भीमताल विधानसभा क्षेत्र के ओखलकांडा, धारी, रामगढ़ व भीमताल की आपदा से कई मोटर मार्ग क्षतिग्रस्त हुए है जिस कारण आवागमन में काफी परेशानियो का समाना करना पड़ रहा है। मंत्री कैड़ा ने कहा प्राधिकरण के कारण स्थानीय लोगो को अपना मकान, दुकान या अन्य निर्माण कार्यों मे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मंत्री राम सिंह कैड़ा ने मुख्यमंत्री से आपदा से क्षतिग्रस्त मोटर मार्गो के पुनः निर्माण कार्य के लिए आपदा मद धनराशि करने, पहाड़ में स्थानीय लोगों को मकान, दुकान, अन्य निर्माण कार्यों में प्राधिकरण के नियमों मे सरलीकरण करने या पहाड़ से प्राधिकरण समाप्त करने की मांग की, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। साथ ही मंत्री कैड़ा ने भीमताल विधानसभा क्षेत्र की अन्य समस्याओं का समाधान करने की मांग की।

डीएम के निर्देश पर मेडिकल स्टोर में ताबड़तोड़ छापेमारी

रुद्रपुर। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया से प्राप्त आदेशों तथा उप औषधि नियंत्रक, के निर्देशन में उपजिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह काशीपुर के नेतृत्व में औषधि विभाग, ऊधमसिंह नगर एवं नैनीताल तथा पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा काशीपुर स्थित विभिन्न थोक मेडिकल प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की कार्यवाही की गई।छापेमारी के दौरान जय लक्ष्मी सर्जिकल, काशीपुर एवं बंसल फार्मास्यूटिकल, काशीपुर पर ट्रामाडोल के क्रय के सापेक्ष विक्रय एवम पेमेंट का सत्यापन ना पाए जाने पर दोनों प्रतिष्ठानों के औषधि संबंधी क्रय–विक्रय पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगाते हुए दुकान को बंद करने की कार्यवाही की गई। इसी क्रम में यूनिक सर्जिकल मोहल्ला अल्लिखाँ के फ़र्म स्वामी के मौके पर भाग जाने व बुलाने पर भी नहीं आने पर प्रशासन द्वारा फर्म को सील की जाने की कार्यवाही की गई।

सम्पादकीय...

चीनी के बढ़ते मूल्य

चीनी के बढ़ते मूल्यों का संज्ञान लिया जाना आवश्यक था, लेकिन अच्छा होता कि सरकार तभी चेत जाती, जब चीनी के दाम बढ़ने शुरू हुए थे। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि बीते दो महीनों में चीनी के मूल्य लगभग 40 प्रतिशत बढ़ गए हैं। सरकार ने इसका कारण खराब मौसम की वजह से गन्ने की फसल को नुकसान और उसके चलते चीनी के घरेलू उत्पादन में कमी, अंतरराष्ट्रीय बाजार में चीनी के दामों में वृद्धि आदि को बताते हुए इससे स्पष्ट रूप से इन्कार किया है कि पेट्रोल में एथनाल की मिलावट से ऐसा हुआ है। उसके अनुसार एथनॉल के लिए इस्तेमाल होने वाली चीनी का हिस्सा घटा है।

उसने यह भी साफ किया कि देश में उत्पादित होने वाले एथनाल का लगभग तीन–चौथाई हिस्सा अनाज और खास तौर पर मक्के से आता है। इस सबके बाद भी उसे यह आभास होना चाहिए था कि त्योहारों को देखते हुए चीनी की मांग बढ़ेगी और जमाखोरी करने वाले इसका लाभ उठा सकते हैं। ध्यान रहे कि एक बार जब किसी आवश्यक वस्तु के दाम बढ़ने लगते हैं तो उन्हें यकायक रोकना संभव नहीं होता। देखना है कि सरकार ने चीनी के बढ़ते दामों पर लगाम लगाने के लिए दस लाख टन चीनी का आयात करने, डीलरों के लिए भंडारण सीमा तय करने और जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करने के जो कदम उठाए हैं, उनके अपेक्षित परिणाम मिल पाते हैं या नहीं? हालांकि सरकार ने यह स्पष्ट किया कि चीनी के मूल्य बढ़ने का कारण एथनाल नीति नहीं है, लेकिन विपक्षी राजनीतिक दल यही साबित करने में जुट गए हैं। उन्हें यह मौका इसलिए भी मिला, क्योंकि खुद सरकार ने यह माना कि एथनाल मिश्रित पेट्रोल से वाहनों के माइलेज में कमी आती है। सरकार ने जिस तरह यह रेखांकित किया कि एथनाल नीति से चीनी उद्योग को लाभ मिला है और चीनी मिलों की आर्थिक स्थिति सुधरने के साथ गन्ना किसानों को भुगतान की समस्या का समाधान करने में आसानी हुई है, उससे ऐसा लगता है कि वह अपनी इस नीति पर पुनर्विचार नहीं करने वाली। यदि यह मान लिया जाए कि एथनाल नीति चीनी के मूल्य बढ़ने का कारण नहीं है तो भी इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती कि ई–20 ईंधन विवाद का मुद्दा बन गया है। यह सही है कि एथनाल नीति से पेट्रोलियम पदार्थों के आयात में खपने वाली विदेशी मुद्रा बचाने में सफलता मिली है, लेकिन यह सही समय है कि इस नीति पर नए सिरे से विचार किया जाए और यह देखा जाए कि विदेशी मुद्रा की जो बचत हो रही है, वह कुल मिलाकर कितनी प्रभावी सिद्ध हो रही है। यह भी देखना होगा कि एथनाल नीति खाद्य सुरक्षा के लिए कोई संकट तो पैदा नहीं करने वाली। इसका आकलन भी किया जाना चाहिए कि क्या ई–20 ईंधन पर्यावरण की रक्षा में सहायक बन पा रहा है?

ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एम.यू.वाई. चौपाल का शुभारंभ

सीएम धामी ने लखपति दीदी" से "करोड़पति दीदी" बनने के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए किया प्रेरित

कुमाऊं जनसन्देश ब्यूरो

भीमताल। मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के व्यापक प्रचार–प्रसार, ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ावा देने तथा इच्छुक उद्यमियों को प्रशिक्षण, क्षमता वर्धन, वित्तीय सहायता एवं मार्केट लिंकेज की जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुक्रवार को विकास भवन भीमताल में "एम.यू.वाई. चौपाल" कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ किया गया।

कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन मुख्य अतिथि अध्यक्ष जिला पंचायत दीपा दरम्वाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि ब्लॉक प्रमुख हरीश बिष्ट, भाजपा मंडल अध्यक्ष कमल जोशी एवं मुख्य विकास अधिकारी अरविंद पांडे उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी के निर्देशन में ग्रामीण उद्यमिता को सुदृढ़ करने तथा स्थानीय स्तर पर उद्यमियों को अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने की रणनीति पर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान राज्य स्तरीय मुख्य समारोह का सीधा प्रसारण किया गया, जिसमें उपस्थित लोगों ने मुख्यमंत्री का प्रेरणादायी संबोधन सुना। मुख्यमंत्री ने महिला स्वयं सहायता समूहों के प्रयासों की सराहना करते हुए "लखपति दीदी" से "करोड़पति दीदी" बनने के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। ग्रामीण क्षेत्रों में योजना के व्यापक प्रचार–प्रसार एवं जागरूकता के लिए अतिथियों द्वारा आई.ई.सी. जागरूकता वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह वैन ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां आमजन एवं इच्छुक उद्यमियों तक पहुंचाएगी। एम.यू.वाई. चौपाल में क्षेत्र के लगभग 80 से 100 स्थानीय उद्यमियों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। उद्यमियों को प्रशिक्षण, क्षमता वर्धन, वित्तीय सहायता, उद्यम स्थापना तथा मार्केट लिंकेज से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। इस दौरान स्थानीय उद्यमियों ने अपने अनुभव एवं सफलता की कहानियां भी साझा कीं।

कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना, एनआरएलएम एवं ग्रामोत्थान योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों एवं स्थानीय उद्यमियों द्वारा तैयार किए गए उत्कृष्ट उत्पादों के स्टॉल लगाए गए। अतिथियों ने स्टॉलों का अवलोकन कर स्थानीय उत्पादों की सराहना की तथा उद्यमियों का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने, स्थानीय उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने तथा युवाओं एवं महिला स्वयं सहायता समूहों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई। इसके उपरांत मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के व्यापक प्रचार–प्रसार एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जनपद नैनीताल में संचालित एम.यू.वाई. चौपाल कार्यक्रम के प्रथम दिवस का आयोजन ग्राम पंचायत नौकुचियाताल में किया गया। कार्यक्रम में कुल 65 प्रतिभागियों ने सहभागिता की। कार्यक्रम के दौरान चौपाल की अवधारणा, नामांकन प्रक्रिया, स्थानीय आवश्यकताओं का आकलन, विभिन्न व्यवसायिक अवसरों एवं बिजनेस आइडियाज, उपलब्ध सरकारी सेवाओं तथा सूचना, शिक्षा एवं संचार वैन की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रतिभागियों को स्वरोजगार एवं उद्यम स्थापना के लिए उपलब्ध प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, क्षमता विकास एवं विपणन सुविधाओं की जानकारी प्रदान की गई।

अधिकारियों ने बताया कि एम.यू.वाई. चौपाल के माध्यम से सेवाओं को सीधे गांव–गांव तक पहुंचाया जाएगा, जिससे ग्रामीण युवाओं, महिलाओं एवं इच्छुक उद्यमियों को नए उद्यम स्थापित करने के लिए प्रेरित किया जा सके। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता की संस्कृति को विकसित करना, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित करना तथा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है।

सीडीओ ने किया कपकोट में विकास कार्यों का निरीक्षण

अधिकारियों को दिए कमियों को तत्काल दूर करने के निर्देश

कुमाऊं जनसन्देश ब्यूरो

बागेश्वर। जिलाधिकारी अपूर्वा पाण्डे के निर्देश पर मुख्य विकास अधिकारी नरेश कुमार व जांच समिति के सदस्यों ने कपकोट विकासखंड में विभिन्न विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर कार्यों की गुणवत्ता एवं प्रगति का जायजा लिया। मुख्य विकास अधिकारी ने पिंडारी ग्लेशियर मोटर मार्ग में लोक निर्माण विभाग एवं पीएमजीएसवाई द्वारा सड़क सुरक्षा के लिए किए गए कार्यों की तकनीकी एवं वित्तीय जांच की। साथ ही ग्राम पंचायत पोथिंग में जिला योजना के तहत ₹9.42 लाख की लागत से कुधरिया गधेरे से नैन सिंह के मकान तक निर्मित पैदल मार्ग का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण में सामने आई कमियों पर शीघ्र विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कपकोट विकासखंड कार्यालय भवन, इंदिरा अम्मा भोजनालय एवं निर्माणाधीन बहुउद्देशीय भवन का निरीक्षण किया गया। बहुउद्देशीय भवन में पाई गई कमियों के निराकरण के लिए अधिशासी अभियंता ग्रामीण निर्माण विभाग तथा कार्यालय भवन व इंदिरा अम्मा भोजनालय की कमियां दूर करने के लिए खंड विकास अधिकारी कपकोट को आवश्यक निर्देश दिए।

नैनीताल जिले में मानव–वन्यजीव संघर्ष रोकने को 109 गांव चिन्हित

डीएम रयाल ने दिए गुणवत्तापूर्ण चैनलिंग फेंसिंग एवं सोलर लाइट्स लगाने के निर्देश

कुमाऊं जनसन्देश ब्यूरो

नैनीताल/हल्द्वानी। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने कहा कि जनपद में पिछले वर्ष मानव–वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं में कई लोगों की जान गई है और कई लोग घायल हुए हैं। इसके साथ ही जंगली जानवरों द्वारा कृषि और बागवानी की फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। नैनीताल कृषि एवं बागवानी के लिए प्रसिद्ध जनपद है, इसलिए किसानों की फसल और जान–माल की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने बताया कि मानव–वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए वन विभाग, कृषि एवं उद्यान विभाग की संयुक्त टीम द्वारा पिछले 5 से 10 वर्षों में संघर्ष वाली घटनाओं का अध्ययन कर रेड जोन चिन्हित किए गए हैं। इस वर्ष संघर्ष से सर्वाधिक प्रभावित 109 गांवों का चयन किया गया है। इन रेड जोन वाले गांवों में जहां सघन खेती होती है और लगातार वन्यजीवों के हमले हुए हैं, वहां विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इन चिन्हित 109 गांवों में गुणवत्तापूर्ण चौनलिंग फेंसिंग का कार्य युद्ध स्तर पर कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त खनन न्यास से 2.5 करोड़ रुपये अतिरिक्त उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि चिन्हित गांवों में शत–प्रतिशत फेंसिंग एवं लाइट का कार्य पूर्ण किया जा सके। जिलाधिकारी ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री का भी विशेष फोकस है कि कृषि–बागवानी को संरक्षण दिया जाए। जहां कहीं गांवों में जान–माल का खतरा है, वहां पिंजरे लगाने, सोलर लाइट लगाने और फेंसिंग के कार्य प्राथमिकता से किए जाएं।

कुमाऊं जनसन्देश में समाचार और विज्ञापनों के लिए सम्पर्क करें। मो.9410354318
ताजा अपडेट के लिए क्लिक करें।
www.kumaonjansandesh.com

सम्पादक : विनोद चन्द्र पनेरू
स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक तथा सम्पादक विनोद चन्द्र पनेरू द्वारा भीड़ापानी ओखलकांडा प्रिन्टिंग प्रेस (मोती सिंह), भोलानाथ गार्डन हल्द्वानी (नैनीताल) से मुद्रित तथा हरिपुर लालमणि पो.ऑ- देवलचौड़, हल्द्वानी, नैनीताल (उत्तराखंड) से प्रकाशित। मो. 9410354318
Email:-vinodpaneru123@gmail.com

डीएम रयाल ने छह अपराधियों को किया जिला बदर

नैनीताल/हल्द्वानी। जिला मजिस्ट्रेट ललित मोहन रयाल की न्यायालय द्वारा गुंडा नियंत्रण कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की गई है। आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाए गए छह व्यक्तियों को छह माह के लिए जिला बदर किए जाने के आदेश पारित किए गए हैं। जिला अधिकारी ललित मोहन रयाल ने जानकारी देते हुए बताया कि आसिफ पुत्र सिराजुद्दीन रहमान, निवासी मेडिकल गली, बनभूलपुरा, के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के कई मामले दर्ज हैं। इसी प्रकार इरफान उर्फ शक्ति पुत्र मेहंदी हसन, निवासी गफूर बस्ती, तथा अरशद अली पुत्र स्वर्गीय असगर अली, निवासी शनिबाजार गेट, थाना बनभूलपुरा, के विरुद्ध भी एनडीपीएस एक्ट के कई मामले दर्ज होने के आधार पर कार्रवाई की गई। शाहनवाज पुत्र अशरफ, निवासी इंदिरा नगर, बनभूलपुरा के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट, चोरी एवं आर्म्स एक्ट से संबंधित कई मामले दर्ज हैं। वहीं राहुल बिष्ट उर्फ राहुल थापा पुत्र वीर बहादुर, निवासी गोकुल नगर, थाना काठगोदाम, के विरुद्ध आर्म्स एक्ट, चोरी तथा जुआ अधिनियम से संबंधित आधा दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। इन सभी को छह माह के लिए जिला बदर करने के आदेश पारित किए गए हैं।

रिवर्स पलायन के लिए योजनाओं का करें प्रभावी क्रियान्वयन : धामी

सीएम ने ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग की बैठक में दिए अहम निर्देश

कुमाऊं जनसन्देश ब्यूरो

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन की स्थिति, रिवर्स पलायन को प्रोत्साहित करने, स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने तथा स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने से संबंधित विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई।

बैठक में ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग द्वारा विभिन्न जनपदों में आयोजित की जा रही प्रवासी पंचायतों, पलायन निवारण एवं स्वरोजगार जागरूकता कार्यक्रमों की जानकारी मुख्यमंत्री के समक्ष रखी गई। आयोग के सदस्यों ने पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने तथा रिवर्स पलायन को गति देने के संबंध में विभिन्न महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बैठक में प्राप्त सभी सुझावों पर गंभीरता से विचार करते हुए प्रभावी कार्ययोजना तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में रिवर्स पलायन को प्रोत्साहित करने के लिए सभी विभाग अपनी–अपनी विभागीय गतिविधियों और योजनाओं के माध्यम से समन्वित रूप से कार्य करें। विभागीय योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को स्वरोजगार एवं आजीविका से जुड़ी योजनाओं की जानकारी सरल और प्रभावी तरीके से उपलब्ध कराई जाए। योजनाओं का लाभ लेने के लिए लोगों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों अथवा बैंकों के चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने तथा योजनाओं की जानकारी गांव स्तर तक पहुंचाने पर विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में स्वरोजगार की अपार संभावनाएं हैं। स्थानीय संसाधनों, पारंपरिक ज्ञान और कौशल को रोजगार से जोड़ते हुए युवाओं को अपने गांव में ही आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में ठोस प्रयास किए जाएं। उन्होंने स्थानीय उत्पादों को व्यापक स्तर पर बढ़ावा देने, उनकी गुणवत्ता एवं ब्रांडिंग पर ध्यान देने तथा बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि रिवर्स पलायन केवल रोजगार उपलब्ध कराने से नहीं, बल्कि गांवों में बेहतर आजीविका, सुविधाएं और संभावनाएं विकसित करने से संभव होगा। इसके लिए सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ परिणामोन्मुखी कार्य करना होगा। बैठक में ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग के उपाध्यक्ष श्री एस.एस. नेगी, सदस्य श्री अनिल सिंह शाही, श्री दिनेश रावत, श्री सुरेश सुयाल, श्री राम प्रकाश पैन्यूली एवं श्रीमती रंजना रावत,

सचिव श्री धीराज गर्ब्याल, डॉ० श्रीधर बाबू अद्दांकी, श्री सी. रविशंकर, श्री अहमद इकबाल,अपर सचिव श्री सौरभ गहरवार, श्रीमती अनुराधा पाल, श्री संतोष बडोनी उपस्थित रहे।

रामनगर में जनपद स्तरीय पांच दिवसीय सरस मेला शुरू

हस्तशिल्प, हथकरघा, खाद्य पदार्थ, जैविक उत्पाद, 'लखपति दीदी' द्वारा तैयार किए गए उत्पादों के लगे हैं स्टॉल मेले को लेकर महिला उद्यमियों में दिख रहा उत्साह

कुमाऊं जनसन्देश ब्यूरो

रामनगर। जनपद स्तरीय 'सरस मेला–2026' का शुक्रवार को रामनगर में विधिवत उद्घाटन 'रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट' द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। रामनगर डिग्री कॉलेज मैदान में आयोजित पांच दिवसीय मेले में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए 'स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं' ने अपने उत्पादों के साथ प्रतिभाग किया। मेले में हस्तशिल्प, हथकरघा, खाद्य पदार्थ, जैविक उत्पाद, 'लखपति दीदी' द्वारा तैयार किए गए उत्पादों सहित अनेक स्टॉल लगाए गए हैं, जो मेले का मुख्य आकर्षण बने हुए हैं। विधायक दीवान सिंह बिष्ट' ने अपने संबोधन में कहा कि मैं मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करना चाहता हूं जो हमारी मातृशक्ति है, महिलाओं का उत्थान, उनका सामाजिक और आर्थिक स्तर कैसे ठीक किया जाए, कैसे उनको आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए लगातार प्रयासरत है। 2023–24 में सरस मार्केट का शुभारंभ किया गया था, जिससे महिला समूहों को आर्थिक और राजनीतिक रूप से सहयोग मिला। आज 2026–27 में भी सरस मेले को जिला स्तर पर आयोजित किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा है कि लखपति दीदियां अब करोड़पति दीदी बनें। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर उनके उत्पादों को बाजार और ब्रांड मिले। विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने कहा कि आज पूरे नैनीताल की महिला समूहों का यह कार्यक्रम है। यह प्रधानमंत्री उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। महिलाओं में इस कार्यक्रम को लेकर बहुत उत्साह है और लोग उनके उत्पादों को खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं। मैं महिलाओं को बधाई देता हूं कि वे अपना कार्य इसी प्रकार करती रहें और सरकार के सहयोग से आगे बढ़ें। इस अवसर पर 'मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार पांडे' ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनके उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराना है। सरस मेला ऐसे ही मंच है जहां महिला स्वयं सहायता समूह अपने उत्पाद सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचा सकते हैं। लखपति दीदी योजना के तहत महिलाएं अब आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं और यह मेला उनकी मेहनत का परिणाम है। उन्होंने बताया कि मेले में 50 स्टॉल लगे हैं। इनमें स्वयं सहायता समूहों के 25 और दूसरे उद्यमियों के स्टॉल शामिल हैं। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि जिले की सभी महिला समूहों को इस मंच के माध्यम से अपने उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग के अवसर मिल रहे हैं। विभाग द्वारा उन्हें तकनीकी सहयोग और प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि वे अपने उत्पादों की गुणवत्ता और बढ़ा सकें। इस दौरान विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति से मन मोह लिया। लोकगायिका माया उपाध्याय ने कुमाऊनी गीतों की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख श्रीमती मंजू नेगी, नगर पालिका अध्यक्ष मोहम्मद अकरम, भाजपा जिला उपाध्यक्ष गणेश रावत, मंडल अध्यक्ष भूपेंद्र खाती, किसान आयोग सदस्य संजय डॉर्बी, दिनेश मेहरा, परियोजना निदेशक डीआरडीए शिल्पी पंत, डीडीओ संतोष पंत, सहायक परियोजना निदेशक चंदा फर्त्याल, बीडीओ गिरीश पांडे आदि मौजूद रहे।

"समस्त विश्व में भारत का मान बढ़ाएं, प्लास्टिक पर हो पूर्ण प्रतिबन्ध, ऐसी जन चेतना की अलख जगायें"

स्वतंत्रता दिवस के शुभअवसर पर जिला पंचायत उधमसिंह नगर की ओर से आप सभी जनवपदवासियों को हार्दिक शुभकामनायें।

जनपद उधमसिंह नगर के ग्रामीण क्षेत्र के समस्त व्यवसायियों से अनुरोध है कि वे जिला पंचायत के सम्पत्ति एवं विभव 'कर' एवं लाइसेंस का भुगतान यथाशीघ्र इसी वित्तीय वर्ष में जमा करने का कष्ट करें। जिला पंचायत जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों हेतु सदैव तत्पर है।

जनपद उधमसिंह नगर के समस्त व्यवसायियों/ग्रामवासियों से यह अपेक्षा की जाती है कि सिंगल यूज पालीथिन और प्लास्टिक/ थर्माकोल हानिकारक है। इससे पर्यावरण/स्वास्थ्य को नुकसान होता है। हमें अब संकल्प लेना है कि प्लास्टिक/थर्माकोल आदि से बने उत्पादों का उपयोग नहीं करेंगे।

(कमलेश सिंह बिष्ट) **अपर मुख्य अधिकारी**

एवं

(अजय मौर्य) **अध्यक्ष**

समस्त सम्मानित सदस्य जिला पंचायत उधमसिंह नगर

कार्यालय जिला पंचायत उधमसिंह नगर

पत्रांक: 1294/लेखा–02/जि.पं.उ.सिं.न./2026–27 दिनांक : 12–08–26

कार्यालय नगर पंचायत लालकुआँ, जिला-नैनीताल

80वें स्वतंत्रता दिवस 2026 के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाए देते हुए नगर पंचायत लालकुआँ, जिला–नैनीताल समस्त क्षेत्रवासियों से यह अपील करती हैं कि :–

1. स्वच्छता सर्वेक्षण 2024–25 में नगर पंचायत लालकुंआं के प्रथम स्थान प्राप्त करने पर समस्त नगरवासियों को हार्दिक शुभकामनाओं व स्वच्छता सर्वेक्षण 2026–27 में नगर पंचायत लालकुंआं को पुन: शीर्ष पर लाने हेतु अपना सहयोग प्रदान करते हुए ठोस अपशिष्ट नियम 2026 के निर्देशानुसार अपने घर एवं दुकान का कूड़ा चार भागों में विभाजित करते हरे डस्टबिन में गीला कूड़ा, नीले डस्टबिन में सूखा कूड़ा, लाल डस्टबिन में सैनेटरी कूड़ा एवं काले में कांच, धातु ई–वेस्ट कूडे को एकत्रित कर केवल नगर पंचायत की कूड़ा गाड़ी में ही डाले। खुले में कूड़ा फैंकने से गन्दगी फैलती है और मच्छरों एवं पशुओं द्वारा इसे फैलाने से बीमारियों की सम्भावना बढ़ती है। ऐसे व्यक्ति जिनके द्वारा गन्दगी फैलाई जाती है, उनकी सूचना नगर पंचायत लालकुंआं में दें।
2. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवश्यकतानुसार योजना का लाभ लें। स्व रोजगार प्रारम्भ करने व पूर्व से संचालित व्यवसाय को बढाने के लिए डे–एनयूएलएम योजना का लाभ उठाये।
3. सम्मानित नागरिक होने के नाते नगर पंचायत के करों/दुकान किराया व यूजर चार्जेज का भुगतान समय पर करें।
4. डेंगू मच्छरों एवं जल जनित रोगों से बचाव हेतु मच्छरदानी का प्रयोग करें, फुल आस्तीन के कपडे पहने एवं बच्चों को पहनाये, कूलर का पानी नियमित बदले, पानी जमा होने वाली जगहों पर मिट्टी तेल डालें, टायरों में पानी जमा न होने दे।
5. उत्तराखण्ड सरकार द्वारा लागू समान नागरिक संहिता के अन्तर्गत 26 मार्च 2010 के बाद विवाह करने वालों को विवाह पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है। राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में विवाह पंजीकरण के शुल्क में रु. 250.00 की छूट प्रदान की गयी है। अत: अतिशीघ्र अपने विवाह का पंजीकरण कराये।
6. सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कदापि न करें।

निवेदक– निर्वाचित सदस्यगण– ▶ श्रीमती नेहा आर्या ▶ श्री धन सिंह बिष्ट ▶ श्री योगेश उपाध्याय ▶ श्रीमती शबनम ▶ श्री सुरेश शाह ▶ श्रीमती दीपा हेमन्त पाण्डे ▶ श्री भुवन पाण्डे, **नामित सदस्यगण**– ▶ श्री विनोद श्रीवास्तव ▶ श्री गौरव कपूर ▶ श्रीमती तारा पाण्डे एवं नगर पंचायत परिवार।

ईश्वर सिंह रावत अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत लालकुआं

सुरेन्द्र सिंह लोटनी अध्यक्ष नगर पंचायत लालकुआं

पत्रांक–/ न0पं0/ विज्ञापन–प्रकाशन / 2026–27, दिनांक 14–08–2026

पुख्ता हों आपदा और सुरक्षा प्रबंधन के इंतजाम

मुख्य सचिव ने ली आपदा प्रबंधन के –ष्टिगत कुंभ मेला–2027 की तैयारियों को लेकर बैठक

कुमाऊं जनसन्देश ब्यूरो

देहरादून। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने गुरुवार को सचिवालय में कुंभ मेला–2027 के दौरान आपदा प्रबंधन एवं सुरक्षा व्यवस्थाओं की तैयारियों को लेकर सम्बन्धित विभागों एवं जिलाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने निर्देश दिए कि संभावित आपदाओं एवं आपातकालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सभी तैयारियां पूर्व से पूरी कर ली जाएं, ताकि मेला अवधि में किसी भी आपात स्थिति में त्वरित एवं प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके।मुख्य सचिव ने कहा कि कुंभ मेला–2027 के लिए आपातकालीन कार्ययोजना एवं क्षेत्र–विशिष्ट प्लान तैयार किए जाएं। उन्होंने पूरे कुम्भ क्षेत्र की सेक्टरवार निकासी योजना तैयार किए जाने के निर्देष दिए।

कहा कि क्राउड मैनेजमेंट, ट्रैफिक प्लान, इवेक्यूएशन प्लान और फायर कंट्रोल मैकेनिज्म को लेकर एक समेकित आपदा प्रबंधन योजना तैयार की जाए, जिसमें भूकंप, बाढ़ तथा केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एवं न्यूक्लियर (सीबीआरएन) आपातकाल जैसी संभावित परिस्थितियों के लिए स्पष्ट एसओपी तैयार की जाए। मुख्य सचिव ने बाढ़, भूकम्प एवं सीबीआरएन आपदा प्रबंधन के लिए आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल उपकरणों की खरीद पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका ऑपरेशनल होना, नियमित रखरखाव और सम्बन्धित कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जाना भी आवश्यक है। उन्होंने उपकरणों से सम्बन्धित गैप का आंकलन कर एसडीआरएफ के माध्यम से कुंभ मेला–2027 के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने एटीएस को और मजबूत करने के निर्देश देते हुए कहा कि पर्वों एवं मेले के पीक टाइम को ध्यान में रखते हुए नियमित मॉक ड्रिल आयोजित की जाएं। आपातकालीन परिस्थितियों को वास्तविक रूप से सिम्युलेट कर उनके दौरान अपनाए जाने वाले वैकल्पिक मार्गों एवं रिस्पांस मैकेनिज्म का परीक्षण किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी व्यवस्थाओं का उद्देश्य आपात स्थिति में रिस्पांस टाइम को न्यूनतम करना होना चाहिए।

मुख्य सचिव ने एआई एवं आधुनिक तकनीक के उपयोग पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि कुंभ मेले के दौरान विभिन्न विभागों से प्राप्त सूचनाओं एवं अनुभवों का व्यवस्थित डेटाबेस तैयार किया जाए, ताकि भविष्य के आयोजनों में इसका उपयोग किया जा सके। उन्होंने आवश्यक तकनीकी एवं विशेषज्ञ सहयोग के लिए आईटीडीए, आपदा प्रबंधन विभाग सहित संबंधित संस्थाओं की सहायता लेने तथा आवश्यकता के अनुसार विशेषज्ञों को हायर करने के भी निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कम्युनिकेशन मैनेजमेंट मजबूत किए जाने के निर्देष दिए हैं। उन्होंने कहा कि अफवाहों की रोकथाम के लिए भी प्रभावी व्यवस्था विकसित की जाए। साथ ही मेले के दौरान अतिरिक्त भीड़ एवं पीक टाइम को ध्यान में रखते हुए मोबाइल नेटवर्क की क्षमता बढ़ाने तथा आवश्यकतानुसार अतिरिक्त मोबाइल टावर एवं संचार सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कंट्रोल रूम को मजबूत करने तथा सभी संबंधित विभागों के साथ आवश्यक समन्वय बैठकें कर व्यवस्थाओं को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कुंभ मेला–2027 एक बड़े स्तर का आयोजन है और इसके लिए सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए किसी भी संभावित आपदा से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहना होगा। इस अवसर पर सचिव श्री शैलेश बगौली, श्री नितेश कुमार झा, श्री विनय शंकर पाण्डेय, आयुक्त गढ़वाल श्री आनन्द स्वरूप एवं मेलाधिकारी श्रीमती सोनिका, सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी एवं जिलाधिकारी उपस्थित रहे।

शोध की गुणवत्ता, नवाचार और तकनीकी दृष्टिकोण पर मंथन

यूओयू में दो दिवसीय शोध कार्यशाला का समापन

कुमाऊं जनसन्देश ब्यूरो

हल्द्वानी। उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी के शोध एवं नवाचार निदेशालय द्वारा 18–19 अगस्त को दो दिवसीय शोध कार्यशाला एवं पीएचडी शोधार्थियों की छह माह की प्रगति समीक्षा आयोजित की गई। कार्यशाला का उद्देश्य शोध की गुणवत्ता एवं प्रासंगिकता बढ़ाने, राष्ट्रीय एवं वैश्विक शोध प्रवृत्तियों से शोधार्थियों को परिचित कराने तथा अंतर्विषयक एवं नवाचारी शोध को प्रोत्साहित करना रहा। कार्यक्रम के दूसरे दिन शुभारंभ सुहानी शर्मा की प्रस्तुति एवं संगीत विभाग के सांस्कृतिक कार्यक्रम से हुआ। शोध एवं नवाचार निदेशक प्रो. गिरजा प्रसाद पांडेय ने शोध की गुणवत्ता, सामाजिक प्रासंगिकता और प्रभाव बढ़ाने पर जोर देते हुए शोधार्थियों के लिए 'शोध प्रोत्साहन' पहल की घोषणा की।

तकनीकी सत्र में इंजीनियर नवीन पांगती ने 'रिसर्च डिजाइन एंड सिस्टम्स एप्रोच' विषय पर व्याख्यान देते हुए जटिल समस्याओं के समग्र समाधान में सिस्टम्स एप्रोच, बाइनरी एवं स्पेक्ट्रम थिंकिंग की भूमिका समझाई। उन्होंने उत्तराखण्ड की स्थानीय कला परंपराओं और आधुनिक शोध पद्धतियों के बीच संबंध को भी रेखांकित किया।

आईसीएआर के डॉ. जे.सी. भट्ट ने 'बदलते समय में कृषि अनुसंधान रू चुनौतियां, नवाचार एवं भविष्य की संभावनाएं' विषय पर कृषि अनुसंधान, हरित क्रांति में आईसीएआर की भूमिका तथा कृषि विज्ञान केंद्रों के योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने पर्वतीय कृषि की चुनौतियों के समाधान के लिए मोबाइल तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी तकनीकों के उपयोग की आवश्यकता बताई।

मुख्य अतिथि जी.बी. पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. शिवेंद्र कुमार कश्यप ने शोधार्थियों से पारंपरिक ज्ञान की सीमाओं से आगे बढ़कर स्वतंत्र एवं रचनात्मक चिंतन के साथ शोध करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि तकनीकी विकास के साथ अपनी जड़ों और मूल ज्ञान प्रणालियों से जुड़ाव बनाए रखना आवश्यक है।

विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. नवीन चंद्र लोहानी ने अध्यक्षीय संबोधन में वैश्विक स्तर पर हो रहे शोध एवं उभरती शोध प्रवृत्तियों से परिचित होने तथा शोध की गुणवत्ता और प्रासंगिकता को अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण से मजबूत करने पर जोर दिया। कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन उप निदेशक डॉ. पी.के. सहगल ने किया।

कार्यशाला के उपरांत पीएचडी शोधार्थियों की छह माह की प्रगति समीक्षा की गई। वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गृह विज्ञान, संस्कृत, शिक्षा, पर्यावरण विज्ञान एवं गणित सहित विभिन्न विषयों के शोधार्थियों ने अपने शोध कार्य की प्रगति प्रस्तुत की। संबंधित शोध निदेशकों एवं पर्यवेक्षकों ने शोधार्थियों के कार्य, शोध पद्धति, दिशा एवं आगामी कार्ययोजना की समीक्षा कर आवश्यक अकादमिक सुझाव दिए। दो दिवसीय आयोजन ने शोधार्थियों को विविध विषयों के विशेषज्ञों से संवाद, नवाचारी शोध दृष्टिकोण तथा अपने शोध कार्य के अकादमिक मूल्यांकन का अवसर प्रदान किया। कार्यशाला ने विश्वविद्यालय में अंतर्विषयक, नवाचारी और वैश्विक दृष्टिकोण से समृद्ध शोध संस्कृति विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

धान खरीद की तैयारी में जुटा उधमसिंहनगर प्रशासन

01 अक्टूबर से होगी खरीद, ,जुलाई से जारी है किसानों की पंजीकरण प्रक्रिया

कुमाऊं जनसन्देश ब्यूरो

रुद्रपुर। जिले में धान खरीद की प्रक्रिया को पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए जिला प्रशासन ने युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। आगामी 01अक्टूबर से धान खरीद प्रारम्भ होगी,जुलाई माह से किसानों का पंजीकरण प्रक्रिया प्रारंभ हो गया है और अब तक भारत ऐप के माध्यम से 1863 किसान अपना पंजीकरण करा चुके हैं। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने गुरुवार को किसान व किसान संगठनों के साथ बैठक कर सभी किसानों से समय रहते पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने की अपील की। जिलाधिकारी ने कहा कि किसानों की एफसीआई (भारतीय खाद्य निगम) से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रशासन किसानों की हर समस्या के समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। धान खरीद के दौरान किसानों की शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु अपर जिलाधिकारी को नोडल अधिकारी तथा मुख्य कृषि अधिकारी को नामित किया गया है,जो मौके पर ही किसानों की समस्याओं का समाधान करेंगे।

जिलाधिकारी ने किसानों को संपूर्ण धान खरीद प्रक्रिया को आपसी समन्वय के साथ सुगम और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने का भरोसा दिया। साथ ही जिलाधिकारी ने अधिकारियों को क्रय केंद्रों पर किसानों द्वारा लाए जाने वाले धान की खरीद व सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त और पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। तथा किसानों की किसी भी समस्या या शिकायत के समाधान हेतु दूरभाष नंबर 9412987380 को भी जारी किया गया। आरएमओ लता मिश्रा ने बताया कि किसानों के पंजीकरण को आसान बनाया गया है। आधार कार्ड से किसानों का पंजीकरण कराया जा रहा है। साथ ही पंजीकरण,भुगतान व एमएसपी के बारे में भी किसानों को गांव गांव जाकर जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि धान खरीद के लिए किसानों का पंजीकरण जुलाई से शुरू हो गया है,वर्तमान तक भारत एप के माध्यम से 1863 किसानों द्वारा पंजीकरण कराया चुका है।किसानों को रजिस्ट्रेशन के लिए खतौनी, आधार कार्ड, बैंक खाता और पंजीकृत मोबाइल नंबर अनिवार्य है। साथ ही किसान अपना पंजीकरण अपने मोबाइल फोन के माध्यम से भारत एप एवं मंडी और सीएससी सेंटर से भी करा सकते हैं। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि भुगतान प्रक्रिया को भी सरकार ने सरल किया है। धान खरीद पर सीधे भुगतान किसान के खाते में किया जाएगा। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी दिवेश शासनी, क्षेत्रीय खाद्य आयुक्त टीएस मर्तोलिया,अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय,मुख्य कृषि अधिकारी डॉ.वीके यादव,मुख्य उद्यान अधिकारी एसके शर्मा, एसएमओ कौशल कुमार, दीपक कुमार, केसी आर्या, जगदीश क्लोनी, ओम नारायण मिश्रा, डिप्टी आरएमओ वरुण कुमार, सचिव मंडी योगेश तिवारी, विनोद चंद पलड़िया, जिला प्रबंधक यूसीएफ संजय आर्य, एनसीसीएफ संतोष कुमार, नीरज सिंह सहित किसान यूनियन के पदाधिकारी एवं किसान उपस्थित रहे।

एसआईआर अभियान को पारदर्शी एवं समय पर पूरा करने के निर्देश

कुमाऊं जनसन्देश ब्यूरो

बागेश्वर। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान को प्रभावी, पारदर्शी एवं समयबद्ध ढंग से संपन्न कराने के लिए शुक्रवार को जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अपूर्वा पाण्डे की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में एसआईआर की प्रगति तथा दावे एवं आपत्तियों की सुनवाई की स्थिति की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोई भी पात्र मतदाता मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे। प्राप्त दावे एवं आपत्तियों का नियमानुसार निष्पक्ष एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील की कि यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल होने से छूट गया है, तो इसकी जानकारी संबंधित एईआरओ के संज्ञान में लाएं। जिलाधिकारी ने बीएलए को भी प्रतिदिन सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने के निर्देश दिए, ताकि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष एवं विश्वासपूर्ण वातावरण में संपादित हो। अपर जिलाधिकारी एन.एस. नबियाल ने बताया कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जनपद की दोनों विधानसभा क्षेत्रों में 31 अगस्त 2026 तक दावे एवं आपत्तियों की सुनवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि जनपद में जारी 42,426 नोटिसों के सापेक्ष 29,384 नोटिसों पर सुनवाई पूर्ण कर ली गई है। शेष नोटिसों पर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सुनवाई की कार्रवाई जारी है। इस दौरान एसडीएम प्रियंका रानी, सहायक निर्वाचन अधिकारी धनी राम टम्टा, कांग्रेस पार्टी से नरेंद्र सिंह कोरंगा, भाजपा से मदन राम आगरी, सीएओ राजेंद्र उप्रेती उपस्थित रहे।

मीट विक्रेताओं को दिए साफ सफाई के निर्देश

रामनगर। रामनगर में लगातार आ रही मीट और मछली विक्रेताओं की शिकायतों का संज्ञान लेकर खाद्य संरक्षा और औषधि प्रशासन रामनगर, ,नैनीताल द्वारा सराय बाजार स्थित मीट और मछली बाजार के मीट और मछली के दो दर्जन खाद्य विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। इस दौरान सभी कारोबारियों को प्रतिष्ठान के अंदर फूड लाइसेंस डिस्प्ले में लगाने, मेडिकल फिटनेस करवाने, डीप फ्रिज को रखने और नियमित रूप से उसकी सफाई करने ,शीशे लगाने, स्टेनलेस स्टील के औजार इस्तेमाल करने, फ्लाई कैचर लगवाने ,डस्टबिन रखने व उसकी नियमित सफाई के लिए निर्देशित किया व प्रतिष्ठान के बाहर सफाई व्यवस्था और गुणवत्तायुक्त मीट व मछली विक्रय को लेकर विशेष निर्देश दिए। वहीं मछली विक्रेताओं को बाहर से आने वाली मछली के भंडारण के संबंध में कोल्ड चौन को बनाए रखने, कितनी मात्रा में और उसको कहाँ से मंगवाया जा रहा है उसका रिकॉर्ड रखने के लिए निर्देशित किया।